



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 नवम्बर, 1992/16 कार्तिक, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोकायुक्त कार्यालय

(आंच आयोग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 अक्टूबर, 1992

संख्या 05 (ई) 5-2/92-लोका (15-ए).—हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सूचित किया गया है कि 21 मार्च, 1992 को ऊना में हुए मैड़ी मेले में श्रद्धालुओं तथा वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल में झड़प हुई थी,

और यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस बल ने अभिकथित रूप में अपने प्राधिकार का दुरुपयोग किया,

श्रद्धालुओं की पिटाई की और अनुचित रूप से धार्मिक स्थान की पवित्रता का अतिक्रमण करने का प्रयास किया,

और जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए मैजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया था,

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन होगा कि उक्त घटना जो कि महत्वपूर्ण मामला है, की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाए,

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इस सरकार की पत्र संख्या 0 गृह (ए) ए (9) 24/92 तारीख 23-9-1992 द्वारा माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश से उपर्युक्त घटना की सच्चाई जानने के लिए जांच आयोग के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए उनकी सहमति मांगी थी,

और माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव ने पत्र संख्या 0 5 (ई) 5-2/92-लोका (15-ए) दिनांक 25 नवम्बर, 1992 द्वारा प्रस्तावित जांच करने के लिए माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश की सहमति दे दी गई है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 15-ए के अधीन, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 18-7-1992 में प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना संख्या : गृह (ए) ए (9) 24/92 तारीख 17 जुलाई, 1992 का अधिक्रमण करते हुए लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश को उपर्युक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करने और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर इस निमित्त अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करते हैं :—

- (1) घटना स्थल पर, घटना घटित होने से पूर्व और पश्चात् क्या स्थिति थी,
- (2) क्या तथ्य और परिस्थितियाँ थी जिनके कारण अभिकथित मारपीट पत्थर फेंकने और आगजनी इत्यादि की गई और वहाँ मौके पर तैनात कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले तत्त्व की क्या प्रतिक्रियाएँ थी और अनुक्रियाएँ भी,
- (3) क्या यह सत्य है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने अपने आचरण के विरुद्ध कार्य करते हुए धार्मिक स्थान की पवित्रता का अतिक्रमण किया,
- (4) क्या यह सत्य है कि वहाँ पर चल रहे अखण्ड पाठ में उन्होंने विघ्न डाला और ग्रन्थियों से मारपीट की,
- (5) यदि कोई सुरक्षा कर्मी धार्मिक स्थान के ग्रन्थी की सुरक्षा हेतु तैनात थे तो उन्होंने क्या भूमिका निभाई,
- (6) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना, और
- (7) कोई अन्य विषय जो आयोग की राय में उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में तथ्यों को अभिनिश्चित करने से सुसंगत हो।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की आग यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) में उल्लिखित उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

2. अतः अब यह अधिसूचना लोकायुक्त द्वारा और उनके आदेशानुसार जारी की जाती है कि वह व्यक्ति, जो इस जांच से सम्बन्धित विभिन्न अनुच्छेदों में उपरोक्त विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित शपथ पत्र (पत्रों) तथा जिस विषय में ब्यानकर्ता ब्यान करने में सक्षम हों, आमन्त्रित करते हैं। ऐसे शपथ पत्र (पत्रों) केवल उन्हीं विषयों तक पूर्णतया सीमित होने चाहिए और तथ्यों का विवरण जो कि शपथ पत्र (पत्रों) में दर्शाना हो, मद विषयों से विशेष तौर पर सम्बन्धित होना चाहिए। ऐसे शपथ पत्र (पत्रों) ठीक ढंग से निम्नलिखित प्रकार से सत्यापित होने चाहिए, जैसे—“कि उपरोक्त शपथ-पत्र (पत्रों) में अनुच्छेदों—में वर्णित विवरण मेरी जानकारी के मुताबिक सही है” और यदि विवरण प्राप्त सूचना से लिया गया है “कि अनुच्छेदों—में दिया गया विवरण—(सूचनादात का नाम) निवासी—से प्राप्त सूचना पर आधारित है और मैं इसे विश्वस्ततः सही मानता हूँ।” यदि सूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी कर्मचारी से प्राप्त हो और ब्यानकर्ता उक्तका नाम शपथ पत्र (पत्रों) में नहीं दर्शाना चाहता हो तो सत्यापन इस प्रकार होना चाहिए “अनुच्छेदों—में दिया गया विवरण सकाराई स्त्रोत/स्त्रोतों से लिया गया है।” प्रत्येक मूल शपथ पत्र (पत्रों) तथा इसकी एक प्रतिलिपि सहित इस अधिसूचना के जारी होने के एक मास के भीतर लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय “पाईन्ज ग्रेव भवन” शिमला-171002 में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक दायर होना चाहिए। यदि शपथ पत्र (पत्रों) उपरोक्त ढंग से सत्यापित न किए गए हों या उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय के अन्दर दायर न किए जाएं तो उन शपथ पत्र (पत्रों) पर लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।

3. जब भी ब्यानकर्ता को बुलाया जाए तो वह लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में उपस्थित हों और उसके पास जो भी दस्तावेज मौजूद हों, और इस जांच से सम्बन्धित अन्य सूचना भी प्रस्तुत करें।

आदेश द्वारा,  
राजेन्द्र भट्टाचार्य,  
आयुक्त एवं सचिव,  
लोकायुक्त व जांच आयोग।

## OFFICE OF LOKAYUKTA

(Commission of Inquiry)

### NOTIFICATION

Shimla-171002, the 29th October, 1992

No. 5(E)5-2/92-Loka. (15-A).—WHEREAS; it has been reported to the H. P. Government that a clash between the devotees and the police force deployed for maintenance of law and order at Mairi fair at Una took place on March 21, 1992 ;

AND WHEREAS, it has been alleged that the police force allegedly abused their authority, beat up the devotees and unduly tried to violate the sanctity of the religious place ;

AND WHEREAS, the District Magistrate, Una had ordered a magisterial enquiry to get at the truth behind this incident ;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into the aforesaid occurrence which is a matter of importance ;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh has approached the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh *vide* this Government letter No. Home (A)A(9)24/92, dated 23rd September, 1992 to have his consent for appointment as the Commission of Inquiry to enquire into the truth behind the aforesaid incident ;

And whereas, the Commissioner-cum-Secretary to Lokayukta, Himachal Pradesh has conveyed the consent of the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh for holding the proposed enquiry *vide* letter No. 5(E) 5-2/92-Loka (15-A), dated 25-9-1992;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, in consultation with the Lokayukta, Himachal Pradesh under section 15-A of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) and in supersession of this Government Notification No. Home (A)A(9) 24/92, dated 17th July, 1992 published in the Rajpatra, H.P. (Extra-ordinary) dated 18-7-1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Hon'ble Lokayukta, H.P. as the Commission of Inquiry to enquire into and to report on the following matters in relation to the aforementioned occurrence within a period of 6 months from the date of publication of this notification:—

- (1) what was the situation prevailing on the spot before and after the incident?
- (2) what were the facts and circumstances leading to the alleged beatings, stone throwing and arson etc. ? and what were the reactions and responses of the law and order enforcement machinery deployed at site ?
- (3) whether it is a fact that some of the police personnel by virtue of their conduct violated the sanctity of the religious place ?
- (4) whether it is a fact that they disturbed the recitation of the Akhand Path and beat the Granthis ?
- (5) what was the role played by the security guards, if any, attached to the Granthi of the religious place ?
- (6) To recommend steps necessary for the prevention of reoccurrence of such incidents in future ? and
- (7) any other matter in the opinion of the Commission relevant to the ascertaining of facts relating to the aforesaid occurrence ;

Further, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that having regard to the nature of the enquiry to be conducted and circumstances of the cases the provisions of sub-section (2), (3), (4) and (5) of Section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 5 of the aforesaid Act, is pleased to direct that the provisions mentioned in sub-sections (2), (3), (4) and (5) of Section 5 shall apply to the Commission.

2. Now, therefore, this notification is issued, by and under the order of the Lokayukta, Himachal Pradesh, inviting all persons acquainted with the subject matter of the inquiry to furnish to the Lokayukta, affidavit(s) containing a statement of facts set out in several paragraphs relating to terms of reference, mentioned above, as to which the deponent is competent to depose. Such affidavit(s) must be strictly confined to these matters only and the statements of facts to be set forth in the affidavit(s) must be expressed to be related to particular items of reference. Such affidavit(s) must be properly verified in the following manner, namely "That the statement in paragraphs . . . of the foregoing affidavit(s) are true to my knowledge," and in case the statements

are derived from the information received, "That the statements in paragraphs..... are based on the information received by me from.....(naming the informant) resident of..... and believed by me to be true." If the information has been received from an official from the Government of Himachal Pradesh and the deponent does not desire to disclose his name in the affidavit(s) the verification should be "That that statements contained in paragraphs..... are derived from official source/sources." The original affidavit(s) with a duplicate copy of each must be filed within a month from the date of issue of this notification in the office of Lokayukta, Himachal Pradesh, Pines Grove Building, Shimla-171002, on any working day between the hours of 10.00 A.M. to 5.00 P.M. Affidavit(s) not verified in the manner indicated above or not filed within the date and time specified above, will not be taken into consideration by the Lokayukta, Himachal Pradesh.

3. Also if and when called upto do so, the deponent should attend the office of the Lokayukta and produce documents which he may have in his possession or furnish any further information regarding the subject matter of Inquiry.

By order,

RAJENDAR BHATTACHARYA,  
Commissioner-cum-Secretary,  
(Lokayukta) and Commission of Inquiry,  
Himachal Pradesh.